ये छः पर्चे, इन्दौर मजदूर तथा मध्य भारत कपड़ा मिल
मजदूर फेडरेशन के

---

१. 'तमाम ख्यालात के मजदूर एक हों,
२. 'मालवा मिल के साथियों की जान बचाने को विशाल आन्दोलन उठाओ,' २६-२-५२, इन्दौर

३. 'म. भा. कपड़ा मजदूर फेडरेशन का चौथा अधिवेशन कामयाब बनाओ,

४. 'राजकुमार मिल फौरन चालू करो, ६-५-५२, इन्दौर।

५. 'राजकुमार मिल के मजदूरों की धन तथा अनाज से सहायता करो।

६. 'गुण्डागिरी किसकी १,३,-५२, इन्दौर।

७. 'डबल बाबू कानूनों का विरोध करो।

८. 'मालवा मिल काण्ड, २५।१।५२ इन्दौर।

९. 'इन्दौर के मजदूरों'
१०. 'राजकुमार मिल चालू करो,
११. 'जनता की बचाव पार्टी बनाओ'

---- शिवनारायण श्रीवास्तव

कम से कम ३५ रुपया बुनियादी पगार पर स्टेण्डर्ड
स्थाई अज्ञाओं में बदल  बेकारी भत्ता ● छटनी की रोक
मजदूरों के लिये मकानात आदि मांगो को हासिल करने के लिये

**तमाम ख्यालात के मजदूर एक हों।**

हिन्दुस्तान के कपड़ा मजदूर आज मालिकों के एक नये हमले का मुकाबला कर रहे हैं। मालिक अपना मुनाफा कायम रखने के लिये मजदूरों पर साल खाते में चार साचे और रिंग में डबल बाजू लादना चाहते हैं। रैशनलाइजेशन और फालतू मजदूर कम करने के बहाने वे हजारों मजदूरों का छटनी कर रहे हैं। सारे देश भर में मजदूरों के अन्दर तेजी के साथ बेकारी फैलरही है।

हमारे मध्य भारत में भी मजदूरों पर मालिकों का दमन और हमले बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। गये पांच सालों में सारे मध्य भारत से करीब १० हजार मजदूर कापले बन्द कर दिये जा चुके हैं। रतलाम उज्जैन इन्दौर आदि केन्द्रों में रिंग खातों में डबल बाजू चलवाई जा रही है। चार सांचों की योजना भी जल्दी ही अमल में आनेवाली है। १९४९, १९५० और १९५१ के बोनस के नामपर मजदूरों के मुंहपर एक दो महिने के बोनस का टुकड़ा फेंका जारहा है। मजदूरों का पूरी तरह दमन करने के लिये और आतंक फैलाने के लिये स्थायी आज्ञाओं के समान खतरनाक हथियार मालिकों के हाथ में दियागया है। बंबई के इंडस्ट्रिअल रिलेशन्स एक्ट जैसे मालिकों के पक्षपाती कानून को मध्य भारत में लागू करवाकर मजदूरों का मुकदमेबाजी की दलदल में लेजाया जा रहा है और इन कानूनों के सहारे मालिकों को मनमानी करने का पूरा मौका मिलरहा है।

इधर मीलों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। मीलों ने युद्ध के जमाने में कमाये हुए करोड़ों के मुनाफे मैनेजिंग एजन्टस ने कमीशन और डिविडेण्ड के रूप में हड़प लिये हैं। मीलों की मशीन सालों पुरानी हो जाने के कारण उन्हें अब बदलना जरूरी है। परन्तु उन्हें बदलने के लिये मशीनें नहीं मिलरही है। हमारे देशकी कांग्रेसी सरकार सिर्फ अमरिका और इंग्लैण्ड से ही मशीनें खरीदना चाहती हैं। ये जगखोर युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं और उनको युद्ध के टैंक तोप और बम बनाने से फुरसत नहीं है। इसके अलावा ये साम्राज्यवादी हमारे देश को अपने पक्के माल के लिये अपना बाजार बनाये रखना चाहते हैं। इस लिये मीलें भी वही पुरानी और बाबा आदम के काल की मशीनों से काम चला रही हैं। इधर देशमें विदेशी और खास कर जापानी कपड़ा आना शुरु हो गया है। इन कपड़े के भाव हमारे देश में बने कपड़े के भावों से सस्ते होने के कारण हमारे देश के कपड़ा मीलें एक बहुतही भयानक होड़का सामना कर रही हैं। इस प्रकार देश के मील मालिकों का आर्थिक संकट गहरा होता जारहा है।

इस आर्थिक संकट को मालिक मजदूरों पर काम बाढ और छटनी लादकर और दूसरी ओर मीलों के खाते या मीलें बन्दकर पैदावार घटाने की जन विरोधी नीति अपना कर हल करना चाहते हैं। आज सूत की पैदावार कम कर देने के कारण हाथकरघे चलाने वाले लाखों बुनकर बेकार हो गये है इस तरह मालिक अपने अर्थ संकट को मजदूरों के सिर उतारने के लिये कोशिश कर रहे हैं।

परन्तु मजदूर मालिकों के इन हमलों का बहादुरी के साथ डट कर सामना कर रहा है। इतनाही नहीं तो वह जनता के हर आन्दोलन में नेतृत्व कर रहा है। बम्बई में अनाज के भाव बढाने की कांग्रेसी नीति के खिलाफ वहां के मजदूरों ने हड़ताल रख कर और अनाज के भाव की [illegible]

के भाव कमकरने के लिये मजबूर किया है। मध्य भारत में भी मालिकों के द्वारा की जानेवाली कामबाढ़ के खिलाफ ग्वालियर के मजदूरों ने १९५१ में ३ सप्ताह की मुकम्मिल हडताल रखी। गये साल उज्जैन में भी डबल बाजू का विरोध करने के लिये मजदूरों ने लम्बी हडताल की। उसी प्रकार बोनस के सवाल पर उज्जैन में मार्च में मजदूरों ने एक दिन की पूरी हडताल की। इन्दौर में राजकुमार मील बन्द करने खिलाफ मजदूरों ने मई में हडताल कर के विशाल प्रदर्शन तथा जुलुस निकाले। इस प्रकार आज मजदूरों मालिकों के हमलों का और सरकार द्वारा जनता पर किये जानेवाले हमले का डट कर मुकाबला कर रहा है। इस कारण मालिकों के हमले रुक गये हैं हालांकि उन्हें पूरी तरह ना कामयाब नहीं किया जा सका हैं।

इस का कारण यह है मजदूरों के अन्दर फूट फैली हुई है। मालिक और सरकार ने दमन और आतंक का सहारा-लेकर पक्का लिया है कि सिर्फ दमन और आतंक से मजदूर को हराया नहीं जा सकता। इसलिये उन्होंने मजदूरों में मजदूर संघ जैसी अपनी जेबी युनियनों के जरिये फूट फैलाई है। आज मालिकों के तमाम हमलों का सिर्फ मजदूर एकता से ही हराया जा सकता है। मजदूरों के बीच आज एकता की जितनी जरूरत है उतनी पहले कभी भी नहीं थी। मजदूरों के पास हमले रोकने का एकता यही एक मात्र हथियार है। इसी मजदूर एकता को हासिल करने के लिये मध्यभारत के तमाम कपड़ा मजदूरों के प्रतिनिधियों का कानफरन्स इन्दौर में १५ और १६ नवम्बर को होने जा रही है।

इस कानफरन्स में प्रान्त भर के मजदूरों के प्रतिनिधी इकट्ठा होकर निम्नलिखित मुख्य मांगे हासिल करने के लिये कार्यक्रम तय करेंगे:—

★ मीलों में काम बाढ और छटनी की रोक हो—मीलों के अन्दर जो कामबाढ की गई है उसमें मालिकों ने मजदूरों की कोई राय नहीं ली है। सच तो यह है कि मशिनरियों की रद्दी हालत को देखते यह संभव नहीं है कि मजदूर डबल बाजू या चार सांचे चला सकें। हिन्दुस्तान के टेक्सटाइल कमिश्नर के टेक्निकल सलाहकार श्री गाडगील ने ग्वालियर की मीलों की हालत देखकर रिपोर्ट में लिखा है कि इस मील में डबल बाजू नहीं चलाई जा सकती। इसलिये प्रांत भर में मजदूरों के सिर थोपी जाने वाली इस कामबाढ के खिलाफ प्रान्त व्यापी आन्दोलन उठाकर इसे रोकना पड़ेगा।

★ बेकारों को काम दो या भत्ता दो—आज मध्यभारत के कपड़ा मीलों में से १० हजार से अधिक मजदूर बेकार हैं इन बेकारों को काम दिलाने की कोई भी व्यवस्था सरकार या मालिकों के पास नहीं है। इसलिये बेकारों को जब तक ये बेकार हैं बेकारी भत्ता दिया जाना जरूरी है। बेकारी भत्ते की मांग हासिल करने से हम बेकारी पर रोक लगा सकते हैं। आज तमाम पूंजीवादी देशों में बेकार मजदूरों को बेकारी भत्ता दिया जाता है।

★ १९४९, १९५० और १९५१ के सालों का बकाया बोनस दिया जाय और हर साल बोनस मिलने का हक मंजूर किया जाय—जब तक मजदूरों को अपना और अपने कुटुम्बियों को रहन सहन के लिये जरूरी जीवन वेतन नहीं दिया जाता है तब तक रहन सहन के खर्च और मिलने वाली पगारों के बीच पड़ने वाली खाई को पाटने के लिये बोनस

इस मांग को उठाना और यूनियन की मान्यता को यह [illegible] धुन्दी खतम करना जरुरी है।

★ मालिक तथा सरकार के खर्च से मजदूरों के हित का प्राविडेण्डफंड, सामाजिक बीमा आदि योजनाएं लागू की जाय केन्द्रिय सरकार ने १ नवम्बर से तमाम मीलों के लिये प्राविडेण्ड फंड योजना लागू की है। उसके अनुसार मजदूरों की कुल पगार से रुपये में से एक आना कटने वाला है। पहले ही मजदूरों को नाकाफी पगार मिलती हैं। एक मायने में यह योजना मजदूरों की पगार काट है इस योजना में मजदूर को२०साल की नौकरी बाद ही फायदा मिलने वाला है। इस का पूरा नियन्त्रण सरकार के हाथ में रहने वाला है। इस प्रकार इस योजना में मजदूरों के हित में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। इस लिये यह जरुरी है कि इस योजना में बदल किया जाय। इस बदल के अनुसार मजदूर को मिलने वाली रकम सरकार और मालिकों ने देना चाहिये। मजदूर जबभी और जिस भी कारण से नौकरी छोड़े उसे यह जमा की हुई रकम मिलना चाहिये। इस योजना को जनवादी तरीके से चुनी गई मील कमिटियों के जरिये अमल में लाना चाहिये।

★ मजदूरों के लिये मकान-मजदूर आज जिन कोठडियों में जिन्दगी बसर करते हैं वे जानवरों को भी रहने लायक नहीं है। मजदूरों का गाढीक माई में से ही उज्जैन और इन्दौर के मालिकों ने मजदूरों के घर बनाने के नामपर साठ लाख रुपया जमा रखा है जिसपर सालाना एक लाख रुपया व्याज कमाते हैं। इन रुपयों से मजदूरों के लिये घर बांधे जाने चाहिये। परन्तु ये बंधे हुए घर या चालों की व्यवस्था मालिकों के नहीं बल्कि मजदूर कमिटियों के हाथ में होनी चाहिये। यह मांग जल्दी ही मंजूर की जाना चाहिये।

इन खास मांगों पर यह कानफरन्स विचार करेगी और इन्हें हांसिल करने के लिये किस प्रकार प्रान्त भरके मजदूरों की एकता कायम करके विशाल आन्दोलन खड़ा किया जा सकता है इस का कार्य क्रम तय करेगी।

आज दुनिया में युद्ध के खतरा फिर बढ़ रहा है। अमरिका पूरे जोर शोर से युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है और चाहता है कि हिन्दुस्तान को भी इस में घसीटा जाय। उसपर आया हुआ अर्थ संकट हमारे देश की अर्थ नीति का अमरिकी और अंग्रेजी साम्राज्यवाद की युद्ध नीति से जुड़े हुए होने का परिणाम है। इसी कारण हमें कल कारखाने खोलने के लिये मशीनें नहीं मिल रही हैं जबकि रूस और सोवियत-पोलेण्ड चेकोस्लावाकिया युनियन, पोलण्ड,आदि युद्ध विरोधी और शान्ति प्रिय देश हमें हर प्रकार की मशीनरी देने और हमसे व्यापार करने को उत्सुक है। हमें कांग्रेसी सरकार को मजबूर करना है कि वह युद्ध नीति से अपना नाता तोडकर इन शान्ति प्रिय देशों से व्यापारिक समझौते करे और मशीनें हांसिल करे। युद्ध नीति का विरोध करके ही हम कपड़ा उद्योग को आगे बढा सकते हैं।

इन तमाम उद्देश्यों को हांसिल करने के लिये मजदूर वर्ग की एकता जरूरी है ताकि वह अपनी मांगे हांसिल करते हुए जनता के आन्दोलन में शामिल कर सके। आज हर ख्यालात के मजदूर को फिर वह किसी भी युनियन में हो किसी भी राजनीति को मानता हो। किसी भी धर्म या जाति का हो, उपर की मांगे हासिल करने के लिय एक होना है। इस एकता के सिवा मजदूरों के पास ऐसा कोई कारगर हथियार नहीं है जिससे वह अपनी मांगे हांसिल कर सकता है और मालिकों के हमलों को खत्म कर सकता है।

इसलिये इस कानफरन्स में प्रान्त भरके कपडा मील मजदूरों ने तथा उनके नेताओं ने इकट्ठा होकर कानफरन्स की कार्यवाही में पूरी तरह हाथ बटाना चाहिए और अपनी मांगे हांसिल करने के लिये एक होना चाहिए।

शिवनारायण श्रीवास्तव

# मालवा मील के साथियों की जान बचाने का विशाल आन्दोलन उठाओ !

मालवा मील कान्ड के साथी बाबू रेमन्या और मदनलाल की फांसी की सज़ा के खिलाफ सुप्रिम कोर्ट में की गई अपील खारिज हो गई है। अब राष्ट्राध्यक्ष बाबू राजेन्द्रप्रसाद और राजप्रमुख ही इन साथियों की जान बचा सकते हैं। जिसके लिये अर्जियाँ भेजने की कार्यवाहियां की जा रही हैं। अर्जियाँ भेजने से ही ये साथी नहीं बच सकेंगे उनके लिये विशाल आन्दोलन भी खड़ा करना ज़रूरी है।

मालवा मील में बाइयों की छंटनी होने के सवाल पर जो आन्दोलन छिड़ा था और जिसमें एक पुलिस अफसर और कान्स्टेबल घायल होकर मर गये थे उसी आन्दोलन के सिलसिले में इन साथियों को यह सज़ा हुई है।

इन साथियों की जान बचाने के लिये किसी भी संस्था या पार्टी की राजनीति घुसेड़ने की आवश्यकता नहीं है। मजदूर सभा ने बिना किसी भेदभाव के इन साथियों की जानें बचाने के लिये लगातार मेहनत की है।

जब इन साथियों पर मुकदमा चल रहा था तब मजदूर संघ के १७ आगेवानों ने चश्मदीद गवाह के नाते झूठी गवाहियाँ दीं। जिनमें से ७ गवाहियां कोर्ट ने झूठी शाबित की। इस प्रकार से इन साथियों को अपने स्वार्थ के लिये मौत की ओर ढकेलने में मजदूर संघ का हाथ रहा है।

आज उसी मजदूर संघ के नेता मसीहा बनकर इन साथियों से सौदेबाज़ी कर रहे हैं। रामसिंहभाई ने इन साथियों से कहा कि वे एक ही शर्त पर इनकी जान बचाने की कोशिश करने को तैयार हैं बशर्ते कि वे लिखकर दे दें कि अब ये साथी स्वतन्त्र मजदूर पंचायत से कोई सम्बन्ध न रखेंगे और मजदूर संघ में शामिल हो जायेंगे।

जो साथी गये ६ माह से काल कोठरियों में बन्द हों; जिन्हें आँखें खुलते ही सामने ही फांसी का फन्दा दिखता हो उनके साथ इस तरह की सौदेबाज़ी करना सिर्फ मौत के सौदागर के लिये ही संभव है।

राजनीति और अपने स्वार्थ को बीच में लाकर इस प्रकार की धोखेबाजी न करते यदि मजदूर संघ और उसके नेता आज भी इन साथियों की जान बचाने के आन्दोलन में शामिल हो जाते तो भी कहा जा सकता था कि दिन भर को भूला शाम को तो भी कम से कम लौट कर आ गया ! परन्तु संघ और उसके नेता इस प्रकार की इन्सानियत की बात करने के आदि नहीं है।

मजदूर सभा ने मालवा मील कांड बचाव कमिटी में आज दिन तक काम किया है और आगे भी करती रहेगी। उसके प्रयत्न से अ० भा० ट्रेड युनियन काँग्रेस के सेक्रेटरी का० डाँगे ने इस कमिटी की मदद के लिये विश्व-मजदूर संघ की ओर से १०० रु. भेजे। नेपाली किसान काँग्रेस ने २५ रु भेजे। इसके अलावा मोज गेट सिनेमा प्रोग्राम आदि करके भी रकम इकट्ठा की गई। यह रकम सुप्रिम कोर्ट की कार्यवाही में खर्च हुई।

रामसिंह भाई ने मजदूरों को आदेश दिया है कि मील में रोज दो मिनिट प्रार्थना करो—वे बाकी सब कुछ कर लेंगे परन्तु इससे इन साथियों की जान नहीं बचेगा। इसलिये मजदूर सभा प्रान्त के और देश के तमाम जनता और जन संस्थाओं और ट्रेड युनियनों से अपील करती है कि मीलों मीलों में मोहल्लों मोहल्लों में शहरों में इन साथियों की जान बचाने के लिये आम सभाओं में प्रस्ताव दस्तखत आन्दोलन आदि करके राजप्रमुख और राष्ट्राध्यक्ष के पास उन्हें भेजिये। १९४२ में अष्टीचिमूर और अभी तेलंगाना के बहादुर साथियों की जान इसी प्रकार जनता के विशाल आन्दोलन ने बचाई है। आज जनता का विशाल आन्दोलन ही इन साथियों की जान बचा सकता है। हर जगह आवाज बुलन्द करो।

**फांसी के फन्दे टूटेंगे !**

**हमारे साथी छूटेंगे !**

शिवनारायण श्रीवास्तव
प्रसिडेन्ट
इन्दौर मजदूर सभा

ता. २६-६-५२

राधाकृष्ण प्रेस आड़ाबाजार, इन्दौर-

छटनी, कामबाढ़, बेकारी और पगार कट के खिलाफ
एक होकर लड़ने के लिये

# म. भा. कपड़ा मजदूर फेडरेशन का चौथा अधिवेशन कामयाब बनाओ

आज सारे हिन्दुस्तान में कपड़ा मील के मजदूरों पर डबल बाजू, चार साँचे; छंटनी और कामबाढ के रूप में मिल मालिकों का हमला शुरू हो गया है। हिन्दुस्तान के बाजार में विदेशी कपड़ा और खासकर जापानी कपड़े के भावों में होड़ शुरू हो गई है। दूसरी ओर हमारे देश को नई मशीनों की जरूरत है। इन मशीनों के लिये कांग्रेसी सरकार सिर्फ अंग्रेज अमरिकी साम्राज्यवादियों पर ही भरोसा रखे हुए हैं और इन साम्राज्यवादियों को युद्ध के सामान बनाने से फुरसत नहीं है। इसके साथ ही हमारे देश पर अंग्रेजों पूंजी का भयानक शिकंजा राजा महाराजाओं को पेन्शनें और जमीनदार जागीरदारों को करोड़ों के मुआवजे हमारे देश का औद्योगिकीकरण रोके हुए हैं। इस कारण देश में बेकारी और गरीबी बढ़ रही है जिससे बाजार में ग्राहक नहीं है और दुकानों में माल भरा हुआ है। बाजार में मन्दी है।

इसके अलावा मील मालिकों की व्यवस्था करने की अयोग्यता फिजूल खर्चा उनके लाखों के कमीशन मीलों के व्यवसाय को और भी हम्र किये दे रहे हैं। हमारी सरकार सोवियत रूस, चीन और दूसरे जनवादी देशों से व्यापार बढ़ाने की नीति नहीं अपनाना चाहती जब कि ये तमाम जनवादी देश हमारे देश से व्यापार करने और हर प्रकार की कल मशीनें आदि देने के लिये पूरी तरह उत्सुक हैं।

मील मालिक अपनी मुनाफाखोरी बरकरार जारी रखने के लिये एक ओर पैदावार घटा रहे हैं। सूत में मुनाफा नहीं है इसलिये सूत की पैदावार घटा रहे हैं जिस कारण हजारों हाथ करघे वाले बेकार हो गये हैं। कपड़ा कम पैदा करने के लिये माल तथा खाते बन्द कर रहे हैं ताकि भाव ऊंचे बने रहें भले ही जनता नंगी रहे। दूसरी ओर विदेशी कपड़े से होड़ कर सकने के लिये कपड़े की लागत कम करना चाहते हैं। उसके लिये वे अपने कमीशन, फिजूल खर्च को कम करने को तैयार नहीं हैं। बल्कि वे मजदूरों पर डबल बाजू और चार साँचे की योजनाएं लाकर कामबाढ और छंटनी कर रहे हैं। इन्दौर की मीलों में गये ४ सालों में ६ हजार मजदूरों की छंटनी हो चुकी है। अभी भी वे करीब ८-९ हजार मजदूरों की और भी छंटनी करना चाहते हैं। राजकुमार मील को फिर बन्द करने का वे इरादा कर रहे हैं। इन सारी योजनाओं को कामयाब बनाने के लिये कांग्रेसी सरकार भी उन्हें पूरी तरह मदद दे रही है। औद्योगिक कानून और उसके अन्तर की स्थायी आज्ञाएं पूरी तरह मालिकों के फायदे में हैं और इन कारगर हथियारों से मालिक मजदूरों की छंटनी करते चले जा रहे हैं।

मालिक ये सारे हमले कामयाबी से अभी तक कर सके हैं उसकी वजह यही है कि कपड़ा मील का मजदूर बंटा हुआ है। इसके पहले भी मालिकों ने जब मजदूरों की रोटी रोजी पर हमला किया है तब मजदूरों ने महंगाई भत्ते के लिये १९४१ में १९४९ की आम हड़ताल में और अभी अभी १९५२ में राजकुमार मील यूनियन ने के लिये एक हफ्ता मालिकों के इस हमले का मुकाबला किया है और मालिकों की योजनाओं को नाकामयाब किया है।

आज मालिक फिर तेजी के साथ हमला कर रहा है और उसके लिये मजदूर एकता की सबसे अधिक जरूरत है। इसी उद्देश्य को मद्दे नजर रखते हुए इन्दौर में मध्य-भारत कपड़ा मील मजदूर फेडरेशन का चौथा अधिवेशन ता० १ और २ नवम्बर को इन्दौर में होने जा रहा है।

इस अधिवेशन में निम्नलिखित बुनियादी मांगों के लिये प्रान्त भर के मजदूर एक होकर आवाज उठायेंगे:—

१. मीलों में कामबन्दी छंटनी को रोका हो और बेकारों को काम दिलाया जाय।

२. १९४९, ५० और ५१ का बकाया बोनस दिया जाय और हर साल बोनस मिलने का हक हो।

३. स्थायी आज्ञाओं को पूरी तरह बदला जाय। मजदूरों को काम से बंद करने का, मील या खाते बन्द कर देने का, आकस्मिक कारण से मील या खाता बन्द हो जाने पर मुआवजा न देने का, बदली वालों को जातू न करने का आदि मालिकों के अधिकार उनके हाथ से छीन लिये जाय।

४. मजदूरों को काम की ग्यारण्टी और मालिक तथा सरकारी खर्च से मजदूरों के हित की प्राविडएंट फंड तथा सामाजिक बीमा योजनाएं आदि लागू की जाय।

५. मजदूरों को अपनी पसन्दगी की यूनियन में शामिल होने का और उसके मारफत अपनी मांग लड़ने का अधिकार मिले और अल्प मत के बल पर किसी खास यूनियन को मान्यता मिलने का अधिकार खत्म किया जाय।

६. कम से कम के बुनियादी पगार ३५ रुपयों का स्टेण्डर्ड कायम किया जाय। और मंहगाई को १०० का सदी पूरा करने वाला महंगाई भत्ता दिया जाय। रेट पर काम करने वाले मजदूरों की पगार तय की जाय।

७. उज्जैन इन्दौर के मालिकों ने मजदूरों के घरों के लिये ६० लाख रुपया दबा रखा है जिसका वे प्रतिसाल एक लाख ब्याज खाते हैं। उससे मजदूरों के लिये घर बनाने की योजनाएं तुरन्त अमल में लाई जाय।

मध्यभारत कपड़ा मील मजदूरों के इस अधिवेशन में शामिल होने के लिये अ० भा० ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के जनरल सेक्रेटरी का० डांगे और श्रीमती अरुणा आसफअली और का० सतसिंह युसुफ को निमंत्रित किया गया है।

इन्दौर के बहादुर मजदूरों ने मालिकों के कई हमलों का एक होकर मुकाबला किया है और मालिकों के हमले खिलाफत एक होने के लिये ही यह अधिवेशन किया जा रहा है।

मजदूर सभा इन्दौर के कपड़ा मील के तमाम मजदूरों से चाहे वो किसी भी दल राजनीति या यूनियन को मानने वाले हों आवाहन करती है कि वे इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिये अपनी पूरी ताकत लगायें—

मजदूर सभा इन्दौर के तमाम कपड़ा मीलों के मजदूरों से अपील करती है कि वे इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिये इस १० तारीख को आठ आने चन्दा देकर स्वागत समिति के सदस्य बनें। साथ ही वे प्रतिनिधि सदस्यता का इस १० तारीख को चार आना और अगली २५ तारीख को चार आना इस प्रकार आठ आना और चन्दा देकर प्रतिनिधि भी बनें और इस अधिवेशन की कार्यवाहियों में पूरी तरह हाथ बटायें।

मजदूर सभा को विश्वास है कि इन्दौर का मजदूर मालिकों के इन हमलों के खिलाफ एकता करने के लिये किये जाने वाले इस अधिवेशन को कामयाब बनाने में कुछ भी उठा न रखेगा।

शिवनारायण श्रीवास्तव

प्रेसिडेन्ट

स्वागत समिति मजदूर सभा इन्दौर.

---

राधाकृष्ण प्रेस आड़ाबाजार इन्दौर.

# राजकुमार मील फौरन चालू करो !

## मील चालू करने और मील बन्दी के नोटिस वापिस लेने के लिये मिली जुली संघर्ष कमेटियां बनाओ !

ता० २ मई से राजकुमार मील बन्द हो गया। करीब ३ हजार मजदूर बेकार हो गये हैं। इसी के साथ हुकमचन्द और कल्याण मील में भी २ जुलाई से मील बन्द होने के नोटिस लग चुके हैं। सारे मजदूर वर्ग पर और आम जनता पर मुनाफाखोरी करने के लिये मालिकों ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया है।

मील बन्द करने के लिये कारण दिये गये हैं कि मीलों में जरूरत से ज्यादा मजदूर हैं, मील को लगातार घाटा हो रहा है और कपड़े के भावों में कमी हो रही है। मजदूरों को मील बन्दी से आतंकित करके मील मालिक उस छटनी की योजना को अमल में लाना चाहते हैं, जो १८ जनवरी और ६ फरवरी १९५२ के मजदूर सन्देश में प्रकाशित हो चुकी है और जिसे अमल में लाने के लिये मजदूर संघ की पूरी राय है।

मजदूर संघ अब काफी ही हल्ला मचा रहा है। परन्तु मान्यता वाली युनियन के नाते मजदूर संघ मील बन्दी की नोटिस लगते ही इस सवाल पर मुकदमा दायर करके मील बन्दी रुकवा सकता था। परन्तु छटनी करवाने और धौंस दपट से मजदूरों से चन्दा वसूलने से मजदूर संघ को फुरसत कहां थी। कांग्रेसी सरकार खुद भी इस मामले में कानूनी दखल करके मील को बन्द होने से रोक सकता था। परंतु मजदूरों की हड़ताल की वार्ता को भी पैदावार के नाम पर मुस्तैदी से अपनी पुलिस फौज से रोकने वाली सरकार इस मील बन्दी को चुपचाप निगल रहा है और मजदूरों को अपने श्रम मंत्री श्री द्राविड द्वारा उपदेश दे रही है कि सीने पर पत्थर रखकर चुपचाप पड़े रहो !!

"सरकार मील कब्जे में लेकर चलाये।" मजदूर संघ के इस नारे की हम पूरी ताईद करते हैं और यदि ईमानदारी से एक मजदूर की भी छंटनी न होने देते मजदूर संघ इस मांग के लिये आन्दोलन छेड़ता है तो हम उसके साथ सहयोग भी कर सकते हैं। परन्तु हमारा अनुभव है कि मजदूर संघ जोड़ तोड़कर समझौता कर लेगा और मजदूरों पर छंटनी का हमला करने में सहयोग देगा। बोनस का अनुभव हमारे

सामने है। मीलों को मुनाफा हुआ है ऐसा अब कहने वाला मजदूर संघ अभी तक यही कहता आया है कि मीलों को घाटा है इसलिये बोनस देने का सवाल कानूनी रूप से नहीं आता।

राजकुमार मील ने १९३९ और १९४५ के बीच एक करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। उसके मैनेजिंग एजण्टों ने इन छः सालों में २१ लाख ८३ हजार का कमीशन लूटा है। आज सुना जारहा है कि इस मील के मैनेजिंग एजण्ट शेअर होल्डरों को डुबाकर दिवाला निकालने जारहे हैं ताकि वे मजदूरों की मनमानी छटनी करके मील को हथिया ले सकें। हमारी मांग है कि सरकार इस बारे में पूरी जांच करे।

राजकुमार मील बन्द हो जाने से जनता को प्रतिमाह ११ लाख वार कपड़े की कमी होगी। मील बन्द करके पैदावार घटाकर मालिक कपड़े की कीमत बढ़वाना चाहते हैं ताकि वे मुनाफाखोरी कर सकें। कपड़े की मीलें बन्द होने से मजदूर तो बेकार होगा ही परन्तु साथ ही मालिकों का यह देशद्रोही रवैया जनता को नंगी रहने को मजबूर करेगा और आम व्यापारी तथा छोटे मोटे दुकानदारों को व्यापारिक संकट के दलदल में उतार देगा।

मील बन्द होनेपर हर पार्टी और खयालात का मजदूर बेकार होगा इसलिये हमारी आम मजदूरों से अपील है कि वे अपने अपने मीलों में तमाम खयालात और राजनीति को अलग रखकर मिली जुली संयुक्त संघर्ष कमेटियां बनाकर मील बन्दी की नोटिस वापिस लेने के लिये संयुक्त आन्दोलन खड़ा करें। श्री द्रविड़ साहब के कहने के अनुसार सिर्फ सीनेपर पत्थर रख कर चुप चाप पड़े रहने से मिल नहीं चलेगा। तमाम मजदूरों की संयुक्त ताकत और एकता ही मीलों के दरवाजे खुलवा के रहेगी।

हमारी आम जनता से भी अपील है कि वे जनता को नंगे रखकर मुनाफाखोरी करने की मालिकों की देशद्रोही नीति के खिलाफ चलाये जा रहे मजदूरों के आन्दोलन में साथ दें और सक्रिय मदद करें।

● इन्दौर के मजदूरों एक हों।
● छटनी नहीं होने देंगे।
● मजदूरों की लड़ाई जनताकी लड़ाई।
● तीन साल का बोनस दो।
● मजदूरों को काम दो।
● जनता को सस्ता कपड़ा दो।

● मील बन्दी के नोटिस वापिस लो ●

मजदूर सभा
ता० ६-५-५२

शिवनारायण
प्रेसिडेन्ट

रामलाल
जनरल सेक्रेटरी

राधाकृष्ण प्रिन्टिंग प्रेस, आड़ाबाजार, इन्दौर.

6. १५४२

# राजकुमार मील के मजदूरों की धन तथा अनाज से सहायता कीजिये !

नागरिक भाइयों !

आप जानते ही हैं कि २ मई से राजकुमार मील के बन्द हो जाने के कारण उस मील के [illegible] हजार मजदूर अपने परिवारों के साथ भुखमरी का सामना कर रहे हैं। मील मालिक [illegible] मुनाफा [illegible] का करार जारी रखने के लिये मील बन्द किये हुए हैं। सरकार [illegible] को मील फौरन चालू कराने के लिए मजबूर करने के बजाय, मजदूरों के [illegible] आन्दोलन पर ही [illegible] वार कर रही है। [illegible] में १४४ धारा लगा दी गई है और मजदूरों के नेताओं और [illegible] को जेल भेज दिया गया है।

आपने मजदूरों के इस आन्दोलन में [illegible] की है। १९४१ के मंहगाई भत्ते की लड़ाई [illegible] में आपने हजारों का धन और अनाज से मदद की थी, १९४७ की हड़ताल में भी [illegible] आवाज मजदूरों की मांग [illegible]। इसी प्रकार मजदूर वर्ग ने भी नागरिक आजादी व सभी आन्दोलनों में [illegible] हिस्सा लिया और कुर्बानियां की हैं। १९४२ के "अंग्रेजो, भारत छोड़ो" के आन्दोलन में [illegible] के [illegible] सुनियत बनाने के आन्दोलन में और [illegible] राजनैतिक आन्दोलन में मजदूर वर्ग कभी भी पीछे नहीं रहा।

इस प्रकार जनता की आजादी के लिये कुर्बानियां करने के कारण मजदूर वर्ग [illegible] मदद पाने का हकदार है। मील चालू कराने की लड़ाई [illegible] जनता की [illegible] लड़ाई है।

मजदूर सभा आपसे [illegible] अपील करती है कि जिस प्रकार भूतकाल में आपने मजदूर आन्दोलन में भरपूर सहायता देकर उसे कामयाब बनाया उसी प्रकार अब फिर दिल खोलकर धन तथा अनाज से मजदूरों की सहायता कीजिये ! इसीके साथ सरकार से अपनी संगठित ताकत से मांग कीजिए कि

○ १४४ धारा खत्म करो !

○ गिरफ्तार मजदूरों को बिना शर्त रिहा करो !

○ राजकुमार मील चालू करो !!!

शिवनारायण श्रीवास्तव
प्रेसिडेण्ट

मजदूर सभा
[illegible]

रामलाल
जनरल सेक्रेटरी

राधाकृष्ण [illegible] इंदौर

# गुण्डागिरी किसकी ?

## रोटी रोजी के संघर्ष में जूझने वाले मजदूरों की या मालिकों के टुकड़खोर मजदूर संघ के नेताओं की ?

२५, २७ और २८ मई को राजकुमार मील खुलवाने के लिये इन्दौर के मजदूरों ने लाल झंडे के मातहत जो विशाल संगठित प्रदर्शन किया उससे घबराकर मजदूर संघ के नेता और कांग्रेस के नगराध्यक्ष बाबूलालजी पाटोदी ने इस आन्दोलन को कम्युनिस्टों की गुण्डागिरी कहकर धुंआधार प्रचार करना शुरू कर दिया। मजदूर संघ के नेताओं ने करीब आधे दर्जन परचे निकाले। इन नेताओं ने सरकार से पुरजोर मांग की कि इस आन्दोलन को सख्ती के साथ कुचला जावे।

सरकार ने भी इस मांग को फौरन पूरा किया क्योंकि यह तो मजदूरों को कुचलने का सवाल था न कि मालिकों को! मालिकों के लिये तो सरकार के पास वैधानिक और शान्तिपूर्ण कानूनी तरीका है जिससे मालिक मील बन्द करके आराम से अपनी कोठी में रहें; मजदूरों को भूखा मारें और जनता को कपड़े से मोहताज कर दें। परन्तु मजदूरों के आन्दोलन के लिये उसके पास एक ही जवाब है वह है डण्डा, १४४ धारा, अंधाधुन्ध गिरफ्तारियां! सरकार ने इसी तरीके पर अमल किया। अब मजदूर इस दमन से दब नहीं सके यह अलाहिदा सवाल है।

मजदूर संघ का जन्म ही मजदूरों को पूंजीवादी असर में दबाये रखने के लिये और उनके गुस्से और आग को कानूनी दलदल में फंसाये रखने के लिये हुआ है। इसलिये मजदूर संघ के नेता कभी भी यह नहीं चाहते कि आम मजदूर अपनी मांगों के लिये कोई भी लड़ाकू आन्दोलन खड़ा करे। मजदूर जब अपनी मांगों का आन्दोलन अपने हाथों में ले लेता है तब उसकी रहनुमाई वही कर सकता है जो मजदूरों को पूंजीवादी शिकंजे से मुक्त करे। ऐसी हालत में जब राजकुमार मील खुलवाने के आन्दोलन को लाल झंडे के मातहत मजदूरों ने अपने हाथ में लेकर हड़ताल करके १० - १० हजार के जुलूस निकालने शुरू किये तो मजदूर संघ के नेताओं को अपनी नैया डूबती दिखाई दी।

यही वजह है कि वे "ताले तोड़कर राजकुमार मील चलाने के" और 'एक दिन की हड़ताल के अपने गरमा गरम नारे भूल गये और उन्होंने इस आन्दोलन को गुण्डागिरी कहकर बदनाम करना शुरू किया।

मजदूर संघ के निकाले हुए परचों में इस हद तक झूठ भरा हुआ है कि उसे पढ़कर कोई भी सत्य अहिंसा के इन पुजारियों के ढोंग से नफरत किये बिना न रहेगा।

मजदूर संघ के मंत्री श्री तिवारी ने "जान बची लाखों पाये" नामक परचे में मजदूरों द्वारा मां बहनों को छेड़ने की बात लिख मारी है। उनका दिमाग इस तरह पागल हो गया कि वे यह भी न सोच सके कि इस जुलुस में भाग लेने वाले १० हजार

मजदूरों का अपमान कर रहे हैं। मजदूर संघ के नेताओं ने इन प्रदर्शनों को इतना जोर शोर से गुण्डागिरी कहना शुरू किया मानो प्रदर्शन में भाग लेने वाले इन्दौर के सारे मजदूर गुण्डे हों और [illegible] सिर्फ दो ही [illegible] आदमी इन्दौर में बच गये हों और वे हैं श्री० गंगारामजी तिवारी व उनके आका श्री रामसिंह भाई !! मजदूर संघ के द्वारा निकाले गये एक भी परचे में पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं है। पुलिस ने मालवा मील पर शान्तिपूर्ण पिकेटिंग करने वाले मजदूरों को ठोकरें मारीं, कल्याणमल मील पर और स्वदेशी पर भी यही किया। पुलिस जांच के [illegible] का० मुकुट बिहारी नाम के मजदूर को पुलिस ने घसीटा जिस कारण उन्हें सख्त चोट आई। पुलिस ने इन दिनों में बेंत, घूंसे और ठोकरों का मजदूरों पर खुलकर उपयोग किया। परन्तु ये सारी बात मजदूर संघ के परचों में खुर्दबीन लेकर ढूंढने पर भी न मिलेगी।

टोपी उछालने जैसी कुछ घटनाएं जरूर हुईं परन्तु वे मजदूर संघ के ही गुर्गों द्वारा की गई थीं। फिर इतने विशाल आन्दोलन में इन छोटी वारदातों को ही बड़ा बताकर गुण्डागिरी कहना तमाम मजदूरों को बदनाम करना है।

मजदूर संघ के नेताओं के थोथे नारों से उकताकर इन्दौर के मजदूरों ने अपनी लड़ाकू विरासत के अनुसार जो विशाल आन्दोलन किया उसके लिये मजदूर सभा उनका हार्दिक अभिनन्दन करती है। मजदूर सभा का १४४ धारा तोड़ कर मील बन्दी के विरोध में आन्दोलन जारी है। मजदूर संघ और कांग्रेस के नेताओं की दमन करने की मांग और मजदूर वर्ग विरोधी रवैये के बावजूद मजदूर सभा का आन्दोलन जारी रहेगा। शासन का दमन, मजदूर संघ के नेताओं की गद्दारी और मजदूरों को काम से बन्द करवाने की साजिश इस मजदूर-आन्दोलन को दबा न सकेगी।

मजदूर सभा इन्दौर के मजदूरों का आह्वान करती है कि अपनी मांगें हासिल करने का सही रास्ता लड़ाकू संघर्ष है। इस संघर्ष को चलाने के लिये और इसे कामयाब बनाने के लिये अपनी अपनी मीलों में संघर्ष कमेटियां बनाओ। तमाम राजनैतिक मतभेद अलग रखकर सभी मजदूर इस संघर्ष में शरीक हों!

मजदूर सभा इन्दौर की जनता और जन संस्थाओं से भी पुरजोर अपील करती है कि वे मजदूर संघ और कांग्रेस के नेताओं द्वारा किये जा रहे झूठे प्रचार को समझें और इन मांगों के लिये अपनी आवाज बुलन्द करें कि:—

● १४४ धारा हटाओ ! ● गिरफ्तार लोगों को बिला शर्त रिहा करो !

● राजकुमार मील चालू करो ! ● मील बन्दी नोटिस वापस लो !!

● मीलों में दमन बन्द करो !!.

शिवनारायण श्रीवास्तव

ता० ३-६-५२ प्रेसीडेन्ट

रामलाल

जनरल सेक्रेटरी, मजदूर सभा

---

राधाकृष्ण प्रिन्टिंग प्रेस, आड़ाबाजार, इन्दौर.

# The Madhya Baharat Textile Workers' Federation

## ( IV Session )

President
Com. Sheonarayan Shrivastava
General Secretaty
Com. Keshiram.

Majdoor Sabha
6, High School Road.
INDORE City.

Dat.................. 195 .

# मध्य भारत सूती मील मजदूर फेडरेशन

अध्यक्ष—

का० शान्ति [illegible]

कार्यवाहक मंत्री—

का० शिवनारायण श्रीवास्तव

मजदूर सभा,

५, हाईस्कूल रोड,

इन्दौर. (मध्य भारत)

# डबल बाजू चलवाने का विरोध करो

मालवा मिल के रिंग खाते में डबल बाजू चलवाना शुरू हुआ है। मजदूर संघ के गंगासिंह भाई, मैनेजर और जॉबर हेडजॉबर ने आपस में साजिश करके बिना नोटिस लगाये गैर कानूनी ढंग से तारीख १८ जुलाई को इक्कट पुलिस का पहरा लगाकर संघ के अगुवानों से डबल बाजू चलवाना शुरू करवा दी है।

मजदूर संघ, मालिक तथा सरकार ने इन्दौर की मिलों के लिये जो छटनी और कामबाद की योजना बनाई है उसका यह पहला हमला है।
यदि इस हमले के खिलाफ डटकर नहीं लड़ा गया तो इन्दौर की सभी मिलों में डबल बाज चल जायेगी।

डबल बाज से रिंग खाते के आधे से ज्यादा मजदूर छांट दिये जावेंगे। दो दो तीन२ खाते मिलाकर जॉबर कम किये जावेंगे। उसके बाद तार वाले, रस्सी वाले और झाड़ूवालों का भी [illegible] जावेगा।

अभी अच्छी रूई का बहाना करके [illegible] जा रहा है। लेकिन जब यह रूई खत्म हो जायेगी, डबल बाज चलानेवाले मजदूरों को पानी पेशाब की भी फुरसत नहीं मिलेगी।

ज्यों ज्यों बेकारी बढ़ेगी मालिक सरदर्द [illegible] जावेंगे, क्योंकि मील के बाहर बेकारों की फौज काम की तलाश में तैयार होगी।

अतः मजदूर सभा, इन्दौर के तमाम मजदूरों से और खासकर मालवा मिल के रिंग के मजदूरों से अपील करती है कि एक होकर रिंग में डबल बाजू चलाने का विरोध करो। मजदूरों की संयुक्त ताकत आने वाली छंटनी और बेकारी को रोक सकती है। मिलीजुली खाता कमिटियां बनाकर संगठित आन्दोलन उठाओ।

रामलाल
[illegible] संचा० मजदूर सभा

शिवनारायण
प्रेसि० मजदूर सभा.

मालवा मील काण्ड के

# साथियों की जानें बचाने के लिये अधिक से अधिक सहयोग तथा धन से सहायता कीजिये

मालवा मील में आज से एक साल पहले जो गोली काण्ड हुआ उसके सारे वाकये से सभी परिचित हैं। मालवा मील में कुछ औरतों की छटनी हुई थी जिसके खिलाफ औरतों ने हड़ताल की और जिनकी मांग के समर्थन में दूसरे मजदूरों ने भी हड़ताल की। मालिकों ने इस मामले को ठीक से सुलझाने के बजाय हमेशा के अनुसार पुलिस से मदद ली। पुलिस और मजदूरों के बीच कुछ तनातनी हुई और पुलिस ने औरतों को भी पकड़ लिये। मामला तेजी से बढ़ गया और दोनों ओर से गरमा गरमी के वातावरण में पुलिस के अफसर श्री जोशी की मृत्यु हो गई।

मामला अदालत में चला और सेशन कोर्ट ने बाबूलाल तंदुवा तथा मदन को फांसी की सजा और दूसरे तीन को दस साल की सजा दी। अपील में हाईकोर्ट ने बाबूलाल और मदन की फांसी की सजा बहाल रखी तथा दूसरे तीन जनों को १० साल की सजाओं के बदले २० साल की सजा दी।

हर एक इन्सान के लिये विचारणीय सवाल यही है कि क्या एक असंगठित भीड़ के द्वारा किये गये कार्य के लिये किन्हीं दो जनों को प्राण दण्ड दिया जाना मानवोचित है? इन मजदूरों ने छंटनी के खिलाफ मजदूरों की रोजी रोटी बचाने के लिये संघर्ष किया था और इसी कारण एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसके लिये दो बहादुर साथी जिन्दगी और मौत के बीच झूल रहे हैं।

अब तो यह मामला सुप्रिम कोर्ट तक ले जाना है। परन्तु साथ ही यह भी जरूरी हो गया है कि एक विशाल जन-आन्दोलन खड़ा कर के सरकार से यह मांग की जावे कि इन साथियों को सजाएं माफ की जावे। इसी उद्देश्य से निम्न पार्टियों ने और व्यक्तियों ने अपने सभी मतभेद भुलाकर के एक मालवा मील कांड बचाव कमेटी बनाई है। हमें विश्वास है कि जो जनता राज्य सत्ता बना और बिगाड़ सकती है वह अपनी संगठित ताकत से उनके सवालों के लिए लड़ते हुए शिकार हुए साथियों की जान भी बचा सकती है। इतिहास इसका गवाह है। १९४८ के दौरान भाखा बिहार के साथियों को व बाद में तेलंगाने के किसान साथियों की मौत की सजायें इसी प्रकार जनता के आन्दोलन ने रद्द करवाई है। और हमें विश्वास है कि एक बार

कानूनी तौर से सुप्रिम कोर्ट में इस मामले की अपील [illegible] है। इन्दौर के कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक मालवा मी[ल] काण्ड बचाव कमिटी ता० २२।१।५२ को बनाई गई है जो इन साथि[यों] की जानें बचाने के लिये जन आन्दोलन चलायगी तथा अपील [और] कानूनी कार्यवाही करने के लिये पैसा भी इकट्ठा करेगी।

इन साथियों की जानें बचाने के लिये विशाल जन आन्दोल[न] उठाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यह कमिटी इस कार्य के लिये सभी जन संस्थाएं तथा गण्य मान्य व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर उनकी मदद से एक विशाल जन आन्दोलन खड़ा करने का प्रयत्न करेगी।

इन्दौर की सभी जन संस्थाओं तथा नागरिकों से मानव[ता के] नाते यह कमिटी अपील करती है कि इन साथियों की जानें बचाने के लिये अधिक से अधिक सहयोग तथा धन दें।

**मालवा मील काण्ड बचाव कमिटी**

लक्ष्मीशंकर शुक्ला, संयोजक ( सोशलिस्ट पार्टी )
गोवर्धनलाल ओझा ( स्वतंत्र मजदूर पंचायत )
होमी दाजी ( कम्युनिस्ट पार्टी )
शिवनारायण श्रीवास्तव ( मजदूर सभा )
रतनलाल उपाध्याय ( [illegible] मजदूर प्रजा पार्टी )
जयराम वनसुडे ( [illegible] कास्ट फेडरेशन )
ओमप्रकाश रावल ( टीचर्स असोसियेशन )
गोपालराव कुमरे ( बोलशेविक पार्टी )
बीरचन्द मेहता ( होजियरी मजदूर पंचायत )

तारीख २५।१।५२

U. M. I.

इन्दौर के मजदूरों -

बिना छंटनी राजकुमार मिल चालू करने और मालिकों के मील न चलाने पर सरकार द्वारा कब्जा किया जाकर मिल चलने की मांगों का समर्थन करते हुए मजदूर सभा ने मजदूर संघ को संयुक्त आन्दोलन के लिये निम्नलिखित पत्र भेजा है -

—— × —— × ——

श्री मंत्री जी,

मजदूर संघ इन्दौर

प्रिय महोदय,

राजकुमार मिल्स बन्द होने के कारण जो परिस्थिति पैदा हुई है उसमें हर मजदूर यूनियन की पूरी दिलचस्पी है और हमारी यूनियन भी इस सवाल

को सुलझाने की ओर अपने कदम बढ़ा रही है।

आपने एक भी मजदूर की छंटनी न करते मिल चलाने की और यदि मिलमालिक मिल न चलाये तो सरकार इस मिल को अपने कब्जे में लेकर चलाने की जो मांग रखी है उनकी हम ताईद करते हैं।

आप इस बात से तो सहमत होंगे कि इस मिल का मसला सुलझाने के लिये तमाम संस्था और मजदूरों की संयुक्त आवाज तथा कार्यवाही आवश्यक है। अतएव हमारा निवेदन है कि इस संबंध में सारी कार्यवाही मजदूरों की संयुक्त एक्शन कमिटी बनाकर की जाय। और इस ओर पहला अमली कदम उठाने के लिये आप ८ तारीख को जो जुलूस निकालने वाले हैं उसे भी संयुक्त रूप से निकाली जाय ऐसा हमारा सुझाव है। यदि आप इस सुझाव से सहमत हों तो हमें इस बारे में शीघ्र सूचित करें ताकि हमारे और आपके प्रतिनिधि मिलकर इस विषय पर विचारात्मक चर्चा करके किसी नतीजे पर आ सकें।

भवदीय -

शिवनारायण श्रीवास्तव
प्रेसिडेंट मजदूर सभा-
इन्दौर।

# राजकुमार मील फौरन चालू करो !

## मील चालू करने और मील बन्दी के नोटिस वापिस लेने के लिये मिली जुली संघर्ष कमेटियां बनाओ !

ता० २ मई से राजकुमार मील बन्द हो गया। करीब ३ हजार मजदूर बेकार हो गये हैं। इसी के साथ हुकमचन्द और कल्याण मील में भी २ जुलाई से मील बन्दी के नोटिस लग चुके हैं। सारे मजदूर वर्ग पर और आम जनता पर मुनाफाखोरी करने के लिये मालिकों ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया है।

मील बन्द करने के लिये कारण दिये गये हैं कि मीलों में जरूरत से ज्यादा मजदूर हैं, मील को लगातार घाटा हो रहा है और कपड़े के भावों में कमी हो रही है। मजदूरों को मील बन्दी से आतंकित करके मील मालिक उस छटनी की योजना को अमल में लाना चाहते हैं, जो १८ जनवरी और ६ फरवरी १९४९ के मजदूर सन्देश में प्रकाशित हो चुकी हैं और जिसे अमल में लाने के लिये मजदूर संघ की पूरी राय है।

मजदूर संघ अब काफी हो हल्ला मचा रहा है। परन्तु मान्यता वाली युनियन के नाते मजदूर संघ मील बन्दी की नोटिस लगते ही इस सवाल पर मुकदमा दायर करके मील बन्दी रुकवा सकता था। परन्तु छटनी करवाने और धौंस दपट से मजदूरों से चन्दा वसूलने से मजदूर संघ को फुरसत कहां थी। कांग्रेसी सरकार खुद भी इस मामले में कानूनी दखल करके मील को बन्द होने से रोक सकती थी। परन्तु मजदूरों की हड़ताल को बातों को भी पैदावार के नाम पर मुस्तैदी से अपनी पुलिस फौज से रोकने वाली सरकार इस मील बन्दी को चुपचाप निगल रही है और मजदूरों को अपने श्रम मंत्री श्री द्रविड़ द्वारा उपदेश दे रही है कि साने पर पत्थर रखकर चुपचाप पड़े रहो !!

"सरकार मील कब्जे में लेकर चलाये !" मजदूर संघ के इस नारे की हम पूरी ताईद करते हैं और यदि ईमानदारी से एक मजदूर की भी छटनी न होने देते मजदूर संघ इस मांग के लिये आन्दोलन छेड़ता है तो हम उसके साथ सहयोग भी कर सकते हैं। परन्तु हमारा अनुभव है कि मजदूर संघ जोड़ तोड़कर समझौता कर लेगा और मजदूरों पर छटनी का हमला करने में सहयोग देगा। बोनस का अनुभव हमारे

सामने है। मीलों को मुनाफा हुआ है ऐसा [illegible] वाला मजदूर संघ अभी तक यही कहता आया है कि मीलों को घाटा है इसलिये बोनस देने का सवाल कानूनी रूप से नहीं आता।

राजकुमार मील ने १९३९ और १९४५ के बीच एक करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। उसके मेनेजिंग एजण्टों ने इन छ सालों में २१ लाख ८२ हजार का कमीशन लूटा है। आज सुना जारहा है कि इस मील के मेनेजिंग एजण्ट शेअर होल्डरों को डुबाकर दिवाला निकालने जारहे हैं ताकि वे मजदूरों की मनमानी छटनी करके मील को हथिया ले सकें। हमारी मांग है कि सरकार इस बारे में पूरी जांच करे।

राजकुमार मील बन्द हो जाने से जनता को प्रतिमाह १६' लाख वार कपड़े की कमी होगी। मील बन्द करके पैदावार घटाकर मालिक कपड़ेकी कीमतें बढ़ाना चाहते हैं ताकि वे मुनाफाखोरी कर सकें। कपड़े की मील बन्द होने से मजदूर तो बेकार होगा ही परन्तु साथ ही मालिकों का यह देशद्रोही रवैया जनता को नंगी रहने को मजबूर करेगा और आम व्यापारी तथा छोटे मोटे दुकानदारोंको व्यापारिक संकट के [illegible] में उतार देगा।

मील बन्द होनेपर हर पार्टी और खयालात का मजदूर बेकार होगा इसलिये हमारी आम मजदूरों से अपील है कि वे अपने अपने मीलों में तमाम खयालात और राजनीतिको अलग रखकर मिली जुली संयुक्त संघर्ष कमेटियां बनाकर मील बन्दी की नोटीस वापिस लेने के लिये संयुक्त आन्दोलन खड़ाकरें। श्री द्रविड़ साहब के कहने के अनुसार सिर्फ सीनेपर पत्थर रख कर चुप चाप पड़े रहने से मिल नहीं खुलेगा। तमाम मजदूरों की संयुक्त ताकत और एकता ही मीलों के दरवाजे खुलवा के रहेगी।

हमारी आम जनता से भी अपील है कि वे जनता को नंगे रखकर मुनाफाखोरी करने की मालिकों की देशद्रोही नीति के खिलाफ चलाये जा रहे मजदूरों के आन्दोलन में साथ दें और सक्रिय मदद करें।

● इन्दौर के मजदूरों एक हों!
● छटनी नहीं होने देंगे।
● मजदूरों की लड़ाई जनताकी लड़ाई।
● तीन साल का बोनस दो।
● मजदूरों को काम दो।
● जनता को सस्ता कपड़ा दो।

● मील बन्दी के नोटिस वापिस लो ●

मजदूर सभा
ता० ९-५-४२

शिवनारायण
प्रेसिडेन्ट

रामलाल
जनरल सेक्रेटरी

राधाकृष्ण प्रिन्टिंग प्रेस, आड़ाबाजार, इन्दौर.

# मजदूर सभा, इन्दौर.

[ अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कांग्रेस से सम्बन्धित ]

प्रेसिडेन्ट का. शिवनारायण श्रीवास्तव

सेक्रेटरी का. रामलाल

नं.

चिमनबाग हाई स्कूल रोड

इन्दौर

ता.——————

## *मालवा मील गोलीकाण्ड के साथियों की जानें बचाने के लिये*

# जनता का बचाव कमिटी बनाओ।

स्वतन्त्र मजदूर पंचायत की ओर से १२ दिसम्बर को एक पर्चा निकाला गया है, जिसमें दी हुई बातें इतनी झूठी और बेबुनियाद हैं कि उसका जवाब देना भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। परन्तु "मालवा मील के साथियों की जानें बचाने के आन्दोलन को चुनाव स्टण्ट मत बनाओ।" यह कह चिल्लाने वालों की ही ओर से चुनाव में फायदा उठाने की गरज में निकाले गये इस पर्चे को जवाब देना और आम मजदूरों के सामने यही बातें रखना जरूरी हो गया है।

इस मालवा मील के गोलीकाण्ड का मामला चलाने की बागडोर श्री० शुक्ला के हाथ में थी और हमारा यह स्पष्ट आरोप है कि उन्होंने अपना व्यक्तिगत तथा अपनी पार्टी का महत्व बढ़ाने के लिये इसका खुलकर उपयोग किया। श्री शुक्ला ने अपने मनमाने तौर से एक बचाव कमिटी बनाई जिसमें अधिकतर बाहर के लोग थे और श्री० पुरुषोत्तमदास त्रिकमदास को उन्होंने उस कमिटी का सभापति बनाया था। दिखाने के लिये उन्होंने का० दाजी और श्री० देव को भी इस कमिटी में लिया। परन्तु इस कमेटी की एक भी मीटिंग न हुई, न उस कमिटी ने संयुक्त रूप से मुकदमे की तैयारी की और न उस कमिटी के सामने कभी भी चन्दे या खर्च का हिसाब रखा गया।

जब तक जेल में मुकदमा चला, श्री० देव करीबन रोजाना मुकदमे में जाते थे परन्तु श्री० शुक्ला ने उन्हें एक भी बार न तो जिरह करने दी और न बहस। श्री० दाजी उस समय ग्वालियर में नजरबन्द हो गये थे और बाद में ग्वालियर विद्यार्थी गोलीकाण्ड की जांच में पैरवी करने के लिये उन्हें ग्वालियर में ही रहना पड़ा। सेशन कोर्ट में मजदूरों के दबाव के कारण श्री० शुक्ला को जिरह वगैरा करने के लिये का० दाजी को मौका देना पड़ा लेकिन उस वक्त भी श्री० शुक्ला ने मामूली तौर से का० दाजी पर कानूनी जिम्मेदारी सौंपी। सेशन में इस मुकदमे की पूरी बहस श्री शुक्ला ने अपनी जिम्मेदारी पर की।

का० चारी को श्री० शुक्ला ने ही बुलवाया। का० चारी को जो दावतें वगैरा देने का जिक्र स्वतन्त्र मजदूर पंचायत के पर्चे में आया है वे खुद श्री० शुक्ला ने ही उनको इस मुकदमे के चन्दे से कोई सम्बन्ध नहीं था। का० चारी ने आकर बहस की पूरी तैयारी की परंतु उन्हें हिंदी अच्छी तरह आती नहीं है और अंग्रेजी में बोलने की इजाजत कोर्ट के द्वारा न दी जाने के कारण वे बहस न कर सके। फिर भी रात भर जागकर उन्होंने श्री शुक्ला को बहस के सारे मुद्दे तय कर दिये थे।